

(viii) यह सुनिश्चित करना कि भरण पोषण के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्रों समुचित संख्या में नागरिकों के आम सम्पर्क वाले कार्यालयों जैसे डाकघर, उपमण्डलीय कार्यालयों, जिला कार्यालयों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, पुलिस थानों आदि में उपलब्ध हों।

(ix) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो सरकार आदेश द्वारा इस आधार पर समय-समय पर उपायुक्त को सौंपे।

(3) उप-नियम (2) में उल्लिखित कर्तव्यों के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे निर्देश संबंधित सरकार या जिले में कार्यरत सांविधिक अधिकरण या कार्यरत निकाय को जारी करने के लिए सक्षम होंगे और विशेषतः निम्नलिखित को, जो अधिनियम, इन नियमों, तथा सरकार के दिशा-निर्देशों के असंगत न हो, जैसा भी आवश्यक हो :—

(i) सरकार में पुलिस, स्वास्थ्य तथा प्रचार विभाग तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभाग के अधिकारियों को;

(ii) भरण-पोषण न्यायाधिकरणों तथा समझौता अधिकारी;

(iii) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्;

(iv) शैक्षणिक संस्थान।

अध्याय-IV

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा

22. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा की कार्य योजना.—(1) पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:—

(i) प्रत्येक थाना अपने क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की एक अद्यतन सूची, विशेषकर जो स्वयं अकेले रह रहे हैं (अर्थात् अपने घरों में किसी उस सदस्य के बिना, जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं), बनायेगा।

(ii) जहां तक संभव हो, थाने का एक प्रतिनिधि, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक सहित नियमित अन्तराल पर ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से मिलेगा। इसके अतिरिक्त उनसे सहायता का अनुरोध प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र मिलेंगे।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय पुलिस द्वारा शीघ्रतापूर्वक सुना जाएगा।

(iv) एक या अधिक स्वयंसेवी समितियां प्रत्येक थाने के लिये बनाई जाएंगी जो वरिष्ठ नागरिकों के बीच नियमित सम्पर्क सुनिश्चित करेंगी, विशेषकर एक ओर तो उनके लिए जो अकेले रह रहे हैं और दूसरी ओर पुलिस तथा प्रशासन के लिए।

(v) पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों को नियमित अन्तराल पर मीडिया में तथा थानों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित करवाएंगे।

(vi) प्रत्येक थाना, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराधों के सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण विवरण एक अलग रजिस्टर में, सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बनाएगा।

(vii) खण्ड (vi) में संदर्भित रजिस्टर जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा तथा किसी थाने को निरीक्षण करने वाला प्रत्येक अधिकारी रजिस्टर में यथा उल्लिखित स्थिति की निरपवाद रूप से समीक्षा करेगा।

(viii) थाना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पुलिस आयुक्त को ऐसे अपराध की सूचना भेजेगा।

(ix) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के हित में उनके द्वारा किए जाने वाले तथा न किए जाने वाले कार्यों की सूची व्यापक रूप से प्रकाशित की जाएगी।

(x) वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर उनके घरेलू नौकरों तथा उनके लिए कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के पूर्ववत्त की शीघ्रता से जांच की जाएगी।

(xi) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुदाय पुलिस, पड़ोसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों में रह रहे व्यक्तियों, युवा स्वयं सेवकों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से बनाई जाएगी।

(xii) पुलिस उपायुक्त पूर्ववर्ती माह के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध हुए अपराधों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक मासिक रिपोर्ट पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे जिसमें माह के दौरान छानबीन की प्रगति तथा पंजीकृत अपराधों का अभियोजन और उठाए गए निवारक कदमों का उल्लेख होगा। पुलिस आयुक्त तिमाही में एक बार रिपोर्टों का संकलन करवाएगा और प्रति तिमाही तथा प्रत्येक वर्ष के लिये उन्हें सरकार को प्रस्तुत करवाएगा इसके साथ-साथ नियम 23 के अन्तर्गत गठित राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा।

अध्याय-V

वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् तथा जिला समितियां

23. वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद्.—(1) राज्य सरकार आदेश से अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सम्बन्धी सरकार को सलाह देने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कार्य करने के लिए राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद् स्थापित कर सकती है, जैसा सरकार उल्लेख करे।

(2) राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

(i) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु —अध्यक्ष पदेन सरकार का मंत्री

(ii) सरकार के विभागों के सचिव जो —सदस्य पदेन अपांगताओं/अशक्तता वरिष्ठ नागरिक के कल्याण स्वास्थ्य, योजना, गृह प्रचार, पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्धित अन्य विषय

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के —सदस्य क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं की उतनी संख्या जो

- सरकार द्वारा नियत की गई हो,
सरकार द्वारा नामांकित किया जाए
- (iv) प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों की —सदस्य
उतनी संख्या, जो सरकार द्वारा
नियत की हो लेकिन सरकार
द्वारा मनोनीत किए
जाने वाले परिषद् के
पदेन सदस्यों से कम न हो।
- (v) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र —सदस्य सचिव पदेन
में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण
के प्रभारी निदेशक।
- (3) राज्य परिषद् की बैठक छः माह में कम से कम एक बार
होगी।

(4) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त राज्य परिषद् के सदस्यों का
कार्यकाल तीन वर्ष होगा जो परिषद् के कार्यकाल की अवधि के साथ
समाप्त होगी।

24. जिला समितियां :—(1) सरकार आदेश से जिला स्तर
पर अधिनियम के प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन संबंधी सलाह देने
के लिए और जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे अन्य
कार्य करने के लिए, जैसा सरकार उल्लेख करे प्रत्येक जिले के लिये
जिला वरिष्ठ नागरिक परिषद् स्थापित कर सकती है।

(2) जिला समिति की बैठक प्रति तिमाही एक बार होगी।

(3) जिला समिति का गठन, सदस्यों का कार्यकाल (पदेन
सदस्यों के अलावा), कार्य पद्धति नियम तथा अन्य सहायक विषय
ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार आदेश से उल्लेख करे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज परिदा, सचिव (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2011

F.No. 30(70)/MTC/DD(SS)/DSW/2009-10/20379-402.—In exercise of the powers conferred by Section 32 read with Section 22(1) and (2) of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to further amend the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009 as following, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Insertion of rules 21, 22, 23 and 24. In the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009, after rule 20, the following rules shall be inserted namely :—

“CHAPTER-III

21. Duties and powers of the Deputy Commissioner.— (1) The Deputy Commissioner shall perform the duties and exercise of the powers mentioned in sub-rules (2) and (3) so as to ensure that the provisions of the Act are properly carried out in his district.

(2) It shall be duty of the Deputy Commissioner to—

(I) ensure that life and property of senior citizens of the district are protected and they are able to live with security and dignity;

(II) oversee and monitor the work of Maintenance Tribunals and Maintenance Officers of the district with a view to ensuring timely and fair disposal of applications for maintenance and execution of Tribunals' orders;

(III) oversee and monitor the working of old age homes in the district so as to ensure that they conform to the standards laid down in these rules, and any other guidelines and orders of the State Government;

(IV) ensure regular and wide publicity of the provisions of the Act, and Central and State Government's programmes for the welfare of senior citizens;

(V) encourage and co-ordinate with municipalities, educational institutions and especially their National Service Scheme Units, organisations, specialists, experts, activists, etc. working in the district so that their resources and efforts are effectively pooled for the welfare of senior citizens of the district;

(VI) ensure provision of timely assistance and relief to senior citizens in the event of natural calamities and other emergencies;

(VII) ensure periodic sensitization of officers of various Departments and Local Bodies concerned with welfare of senior citizens, towards the needs of such citizens, and the duties of the officers towards the latter;

(VIII) ensure that adequate number of prescribed application forms for maintenance are available in offices of common contact for citizens like Post Offices, SDMs offices, District Offices, PDS Outlets, Police Stations, etc.;

(IX) perform such other functions as the Government may, by order, assign to the Deputy Commissioners in this behalf, from time to time.

(3) With a view to performing the duties mentioned in sub-rule (2), the Deputy Commissioners shall be competent to issue such directions, not inconsistent with the Act, these rules, and general guidelines of the Government, as may be necessary, to any concerned government or statutory agency or body working in the district, and especially to the following :—

(I) Officers of the Government in the police, Health and publicity Department, and the Department dealing with welfare of senior citizens;

- (II) Maintenance Tribunals and Conciliation Officers;
- (III) Municipal Corporation of Delhi and NDMC;
- (IV) Educational institutions.

CHAPTER-IV

PROTECTION OF LIFE AND PROPERTY OF SENIOR CITIZENS

22. Action plan for the protection of life and property of senior citizens.—(1) The Commissioner, Police shall take all necessary steps, subjects, to such guidelines as the Government may issue from time to time, for the protection of life and property of senior citizens.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule

(1).—(I). each police station shall maintain an up-to-date list of senior citizens living within its jurisdiction, especially those who are living by themselves (i.e. without there being any member in their household who is not a senior citizen).

(II) a representative of the police station together, as far as possible, with a social worker or valunteer, shall visit such senior citizens at regular intervals and shall, in addition, visit them as quickly as possible on receipt of a request of assistance from them.

(III) complaints/problems of senior citizens shall be promptly attended to, by the local police.

(IV) one or more Volunteers' Committee(s) shall be formed for each police station which shall ensure regular contact between the senior citizens, especially those living by themselves on the one hand, and the police and district administration on the other.

(V) the Commissioner, Police shall cause to be published widely in the media and through the police stations, at regular intervals, the steps being taken for the protection of life and property of senior citizens.

(VI) each police station shall maintain a separate register containing all important particulars relating to offences committed against senior citizens, in such form as the Government may, by order, specify.

(VII) the register referred to in clause (VI) shall be kept available for public inspection, and every officer inspecting a police station shall invariably review the status as reflected in the register.

(VIII) the Police Station shall send a monthly report of such crimes to the Commissioner, Police by the 10th of every month.

(IX) list of Do's and Don'ts to be followed by senior citizens in the interest of their safety will be widely publicized.

(X) antecedents of domestic servants and other working for senior citizens shall be promptly verified, on the request of such citizens.

(XI) community policing for the security of senior citizens will be undertaken in conjunction with citizens living in the neighbourhood Residents' Welfare Association, Youth Volunteers, Non-Government Organisations, etc.

(XII) the Deputy Commissioner of Police shall submit to the Commissioners of Police, a monthly report by the 20th of every month, about the status of crime against senior citizens during the previous month, including progress of investigation and prosecution of registered offences, and preventive steps taken during the month. The Commissioner of Police shall cause the reports to be compiled, once a quarter, and shall submit them to the Government every quarter as well as every year for, *inter alia* being placed before the State Council of Senior Citizens constituted under rule 23.

CHAPTER-V

STATE COUNCIL AND DISTRICT COMMITTEES OF SENIOR CITIZENS

23. State Council of Senior Citizens.—(1) The State Government may, by order, establish a State Council of Senior Citizens to advise the State Government on effective implementation of the Act and to perform such other functions in relation to senior citizens as the Government may specify.

(2) The State Council shall consist of the following members, namely:—

- (i) Minister of the Government in charge of welfare of senior citizens —Chairman, ex-officio
- (ii) Secretaries of Department of the Government dealing with Disabilities, Senior Citizens Welfare, Health, Planning Home, Publicity, Pensions and other subject of concern to the senior citizens —Member ex-officio
- (iii) such number of specialists and activists in the field of welfare of senior citizens, as the Government may determine, to be nominated by the Government —Members
- (iv) such number of eminent senior citizens, as the Government may determine, but not less in number than the ex-officio members in the Council, to be nominated by the Government —Members
- (v) Director in-charge of Senior Citizens Welfare in the NCT of Delhi. —Member-Secretary ex-officio

(3) The State Council shall meet at least once in six months.

(4) Tenure of the members of the State Council, other than ex-officio members, will be three years which will be co-terminus with the term of the Council.

24. District Committee.—(1) The Government may, by order, establish a District Committee of Senior Citizens for each District to advise in effective and co-ordinated implementation of the Act at district level, and to perform such other functions in relation to senior citizens at the district level, as the Government may, specify.

(2) The District Committee shall meet once in every quarter.

(3) Composition of the District Committee, tenure of members (other than ex-officio Members), rules of procedure and other ancillary matters shall be such as the State Government may, by order, specify.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ PARIDA, Secy. (Social Welfare)